



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2016/ज्येष्ठ 26, 1938

No. 192]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2016/JYAISTHA 26, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2016

विषय : मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, सऊदी अरब और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "नैरो वोवेन फेब्रिक" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए याचिका

संख्या 14/23/2015-डीजीएडी.—मै ग्लोबल नानवोवेन्स लि. (जिसे आगे याचिकाकर्ता/आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, सऊदी अरब और चीन जन. गण. (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "नैरो वोवेन फेब्रिक" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

विचाराधीन उत्पाद

2. याचिका में विचाराधीन उत्पाद जीएसएम 25 या उससे कम के पालीप्रोपिलीन से निर्मित नानवोवेन फेब्रिक है। ये नानवोवेन फेब्रिक ऐसे शीट या वेब स्ट्रक्चर के रूप में व्यापक रूप से परिभाषित किये जाते हैं जो यांत्रिक, तापीय या रासायनिक रूप में आपसे में उलझे फिलामेंट से जुड़े होते हैं। ये सपाट, छिद्रित शीटे होती हैं जिन्हें सीधे गले हुए प्लास्टिक से बनाया जाता है। इन्हें बुनाई या कढ़ाई से नहीं बनाया जाता है और इनमें फाइबरों से यार्न में परिवर्तित करना आवश्यक नहीं होता है। विचाराधीन उत्पाद को अनेक विभिन्न प्रकार या किस्मों में उत्पादित किया जा सकता है जो जीएसएम में अंकित फेब्रिक या उस तरीके जिसमें फेब्रिक निर्मित होता है, की मोटाई में अनिवार्य रूप से अलग-अलग होते हैं। उत्पादित प्रक्रिया में

मोल्टेन फेब्रिक को दो गर्म सिलेंडरों में से गुजारा जाता है जो बॉडिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ये या तो स्पन बांड तकनीक में या मेल्ट ब्लोन तकनीक में हो सकते हैं।

3. विचाराधीन उत्पाद को आम तौर पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 56 के अंतर्गत उपशीर्ष 56031100, 56039100 आदि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और उत्पाद का विवरण सभी परिस्थितियों में लागू होगा।

समान वस्तु

4. याचिकाकर्ताओं में अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु समान वस्तु हैं। संबद्ध देशों से निर्यातित और याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नैरो वोवेन फेब्रिक और संबद्ध देशों से आयातित नैरो वोवेन फेब्रिक भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

5. यह आवेदन मै. ग्लोबल नानवोवेन्स लि. द्वारा विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में दायर किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार वे भारत में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में संबद्धवस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं। एस ई जैड में मैसर्स एहल्स्ट्रोम फाइबर कंपोजिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक अन्य निर्माता भी है, जो संबद्ध वस्तुओं का निर्माण कर रहा है और उसने समर्थन पत्र भी दिया है। याचिकाकर्ता ने प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा या उसके किसी संबद्ध पक्ष द्वारा संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन में 'प्रमुख हिस्सा' बनता है इसलिए याचिकाकर्ता नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग की योग्यता को पूरा करता है और घरेलू उद्योग है।

शामिल देश

6. वर्तमान जांच मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, सऊदी अरब और चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य

7. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और उसने नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य को निर्धारित किया है। उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। आवेदकों ने भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके सामान्य मूल्य को निर्धारित किया है।

8. इसके अलावा, आवेदक ने मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड और सऊदी अरब के संबंध में सामान्य मूल्य को इन आधारों पर परिकलित किया है कि वे उक्त देशों में संबंध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे। इसके अलावा, ऐसी सूचना सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध नहीं थी। प्राधिकारी ने इस जाँच शुरूआत के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए परिकलित मूल्य के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर प्रथम दृष्टया विचार किया है।

निर्यात कीमत

9. आवेदकों द्वारा निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएस और आईबीआईएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर किया गया है। कमीशन, समुद्री भाड़े, पट्टन व्यय, अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री बीमा, वैट समायोजन और बैंक प्रभारों के लिए कीमत

संबंधी समायोजनों का दावा किया गया है। जाँच की प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकारी वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से सौदा-वार आयात आकड़ों का भी विश्लेषण करेंगे।

पाटन मार्जिन

10. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हुए संबद्ध देशों के संबंध में पर्याप्त पाटन मार्जिन को दर्शाता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुएं पाटित की जा रही हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंध

11. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए एक नई सुविधा स्थापित की है और जाँच अवधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। आवेदक ने दावा किया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तव में बाधित कर रहा है। आवेदक ने अपने वाणिज्यिक उत्पादन के लिए अवधि हेतु क्षति के विभिन्न मापदंडों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग उत्पादन की शुरुआत से पहले घरेलू उद्योग द्वारा परिकल्पित उचित कीमत वास्तव में कम कीमतों पर उत्पाद की बिक्री करने को बाध्य हुआ है। इस प्रकार आवेदक ने दावा किया है कि उसके वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने के समय भी घरेलू उद्योग बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाया है।

12. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को विभिन्न मापदंडों जैसे समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की बड़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, निरंतर वित्तीय घाटा, निवेश पर आय, नकद प्रवाह, मासूचियों आदि के संबंध में घाटों के तेज होने के कारण पाटित आयातों से वास्तविक क्षति हुई है। विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और संबद्ध आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है। आयातों ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू कीमतों में ह्रास/न्यूनीकरण किया है। घरेलू उद्योग पर आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में मापदंडों जैसे लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ के संबंध में विकृति आई है। घरेलू उद्योग भारी वित्तीय घाटा, नकद घाटा और निवेशों पर नकारात्मक आय उठा रहा है।

13. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियमावली के पैरा 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करना

14. पूर्वोक्त पैराग्राफों को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करते हैं।

जाँच अवधि (पीओआई)

15. इस बात पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता ने मार्च 2015 में परीक्षण उत्पादन और जुलाई 2015 में ही वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत की है, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 जुलाई, 2015 से 31 मार्च, 2016 (9 महीनों) की है। तथापि, क्षति का विश्लेषण वास्तविक कार्यनिष्पादन और प्रक्षेपित अनुमानों/लक्ष्यों की तिमाही वार तुलना के आधार पर किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

**निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**

वाणिज्य विभाग,

जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,

**5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली - 110001**

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

समय-सीमा

18. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना मूल प्रतियों तथा साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

21. गोपनीय या अगोपनीय अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां दो (2) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

22. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

26. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2016

Subject: Petition for initiation of anti-dumping investigations on the imports of “Non Woven Fabric” originating in or exported from Malaysia, Indonesia, Thailand, Saudi Arabia and China PR

F. No. 14/23/2015-DGAD.—M/s. Global Nonwovens Limited (hereinafter referred to as the ‘petitioner/applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of Non-Woven Fabric (hereinafter referred to as the “subject goods”) originating in or exported from Malaysia, Indonesia, Thailand, Saudi Arabia and China PR (hereinafter referred to the “subject countries”).

Product under consideration

2. The product under consideration in the petition is “Nonwoven fabric made of Polypropylene of GSM 25 or less”. These Nonwoven fabrics are broadly defined as sheet or web structures bonded together by entangling filaments mechanically, thermally, or chemically. They are flat, porous sheets that are made directly from molten plastic. They are not made by weaving or knitting and do not require converting the fibers to yarn. The product under consideration can be produced in a number of different types or varieties, which essentially differ in thickness of fabric denominated in GSM, or in the manner in which fabric is formed. The production process involves passing of molten polypropylene through pair of hot cylinders which acts as a bonding agent. This can be either in spun-bond technique or in melt blown technique.

3. The product under consideration is generally classified under Chapter 56 of the Customs Tariff Act under sub heading 56031100, 56039100 etc. It is clarified that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

Like Article

4. The petitioner submitted that subject goods produced by the petitioner companies and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the petitioner. Non woven Fabric produced by the

domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

5. The Application has been filed by M/s Global Nonwovens Limited, as domestic industry of the product under consideration. According to the Petitioner, they are the sole producers of the subject goods in Domestic tariff Area in India. There is another manufacturer but in SEZ namely M/s Ahlstrom Fibre Composites India Pvt. Ltd. who are also manufacturing the subject goods and have given a support letter. The petitioner has certified that there are no imports of the product under consideration by the petitioner or any of its related party from the subject countries. Since the production of the petitioner accounts for "a major proportion" in the total production of the product under consideration in India, the petitioner satisfies the standing and constitutes Domestic Industry within the meaning of the Rules.

Countries involved

6. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from Malaysia, Indonesia, Thailand, Saudi Arabia and China PR.

Normal Value

7. The petitioner has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. In view of the non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules. The applicant has determined the normal value based on cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

8. Further, the applicant has also constructed the normal values in respect of Malaysia, Indonesia, Thailand and Saudi Arabia on the grounds that they were neither able to get any documentary evidence nor reliable information with regard to domestic prices of the subject goods in the said countries. Further, such information is also not available in public domain. The Authority has *prima-facie* considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values as made available by the applicants for the purpose of this initiation.

Export Price

9. The applicant has determined the export price on the basis of data published by DGCIS and IBIS. Price adjustments have been claimed on account of commission, ocean freight, port expenses, inland freight, marine insurance, VAT adjustment and bank charges. During the course of investigation, the Authority will also analyse transaction-wise import data from Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCIS)

Dumping Margin

10. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which show significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the ex-factory export price,

indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Injury and Causal Link

11. The applicant has set up a new facility for production of the product under consideration and commenced commercial production within the investigation period. The applicant has claimed that dumping of the product under consideration in India is materially retarding the establishment of the domestic industry. The applicant has furnished information on various parameters relating to injury for the period for which it has commercial production. The domestic industry is forced to sell the product at prices materially below the fair prices envisaged by the domestic industry before commencement of production. The applicant has thus claimed that even when its commercial production has begun, the domestic industry is yet to find its place in the market.

12. The applicant has claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports exemplified by various parameters such as significant increase in imports in absolute terms as also relative to the production and consumption in India, significant price undercutting, capacity utilization market share, continued financial losses, return on investments, cash flow, inventories, etc. The demand for the product under consideration has increased over the injury period and subject imports have increased in absolute terms. The imports are undercutting the domestic prices. The imports have suppressed/depressed the domestic prices over the injury period. With regard to consequent impact of the imports on the domestic industry, it is noted that performance of the domestic industry has deteriorated in respect of parameters such as profits; return on capital employed and cash profits. The domestic industry is suffering significant financial losses, cash losses and negative return on investments.

13. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Initiation of anti-dumping investigations

14. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Period of Investigation (POI)

15. The period of investigation for the purpose of present investigation is from 1st July 2015 to 31st March 2016 (9 months) considering that Petitioner has commenced trial production in March 2015 and commercial production in July 2015 only. However, the injury analysis is proposed to be carried out on the basis of quarter to quarter comparison of actual performance and projected estimates/targets.

Submission of Information

16. The exporters in the subject countries, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Department of Commerce,
Jeevan Tara Building, 4th Floor
5, Parliament Street
New Delhi -110001

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

18. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

20. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof.

21. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.

22. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

26. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

27. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

28. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Additional Secretary & Designated Authority